रणजीत टाइम्स

इंदौर

शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026

वर्ष 02 | अंक 160 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

वर्षाकाल में जलजमाव को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने ली बैठक

किसी भी स्थिति में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने कलेक्टर श्री वर्मा ने दिए अधिकारियों को निर्देश, जलभराव वाले स्थानों से पम्प लगाकर की जाएगी जल निकासी, लापरवाही पाये जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

इंदौर। इंदौर में वर्षाकाल के दौरान जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने आज व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने वर्षा के दौरान जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी स्थिति में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने। लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उक्त समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के संयुक्त दल बनाये जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, डीसीपी ट्रैफिक श्री राजेश त्रिपाठी, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय सहित नगर निगम, यातायात पुलिस, एमपीआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी नालों, चैनलों, तालाबों के आसपास तथा जलभराव वाले स्थलों की साफ-सफाई तत्काल की जाए ताकि जलभराव व ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने । साथ ही स्टॉर्म वॉटर लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम की सफाई भी प्राथमिकता से की जाए, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही कलेक्टर श्री वर्मा ने सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि आवश्यक पैचवर्क, डामरीकरण एवं सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि बारिश के दौरान गड्ढों एवं जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप भी किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए तथा जहां भी पानी भरने की समस्या हो, वहां तत्काल पंप लगाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि किसी भी स्थिति में जलभराव के कारण यातायात बाधित नहीं होना चाहिए और आमजन की सुगमता एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि चिन्हित दुर्घटना संभावित (एक्सीडेंटल) एवं जलभराव वाले स्थानों पर आज शाम से लेकर कल तक आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित विभाग अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राहत स्थलों की समीक्षा भी की गई। निर्देश दिए गए कि आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविर तत्काल प्रारंभ किए जा सकें, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा पिकनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, पुल-पुलियों पर संकेतक लगाने, बाढ़ की स्थिति में सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित की जाए।

जिले में संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वर्मा ने संबंधित विभागों को पूरी सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का 24×7 संचालन सुनिश्चित करते हुए स्थिति की सतत निगरानी रखें। जिला आपदा प्रबंधन योजना एवं बाढ़ संबंधी आकस्मिक कार्ययोजना की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अद्यतन कार्यवाही सुनिश्चित करें। पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को पूर्ण सतर्कता की स्थिति में रखा जाए। संवेदनशील एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आवश्यक बचाव उपकरण, नाव, राहत सामग्री, चिकित्सा दल एवं अन्य संसाधनों की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नदी, बांध, जलाशय एवं नालों के जलस्तर की सतत निगरानी संबंधित विभागों के समन्वय से की जाए। मौसम संबंधी चेतावनियों एवं जन-सुरक्षा संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया, एसएमएस, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से समय पर कराया जाए। आवश्यकतानुसार राहत शिविरों, सुरक्षित आश्रय स्थलों एवं संभावित निकासी (Evacuation) की तैयारियाँ पूर्ण रखें। जलभराव, सड़क अवरोध, विद्युत, पेयजल, संचार एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की त्वरित बहाली हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित रखें। नागरिकों को नदी, नालों, पुल-पुलियों, जलभराव वाले क्षेत्रों एवं अन्य जोखिमयुक्त स्थानों से दूर रहने तथा अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करने संबंधी सलाह जारी की जाए।

कारण बताओ साहब ?

इंदौर निगम कमिश्नर जी .. कल केवल 2.5 इंच हुई बारिश में ही एक व्यक्ति बह गया , एक थार नाले में गिर गई , सड़के तालाब बन गई , घण्टो लंबा जाम हो गया .. महोदय आप कृपया कर इसका कारण बताए जनता की इसमें क्या गलती है , जनता ऐसा क्या करे जिससे ये सब स्थिति निर्मित न हो कल कई यात्रियों की ट्रेन, बस , फ़्लाइट छुटी होगी, कई एम्बुलेंस जाम में फंस कर रह गई होगी आपने पूरे साल शहर में इनसे निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए और वो कितने सफल हुए, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई ?? कृपया कर महोदय इन स्थिति का #कारण_बताए , कमी कहा रह गई। और जनता से आप और क्या सहयोग चाहते है ? जिससे अभी जुलाई , अगस्त महीने में ऐसी अफरा तफरी न मचे...

एक_आम_इंदौरी

रणजीत टाइम्स के प्रधान संपादक गोपाल गावंडे ने संझा लोकस्वामी के प्रधान संपादक जीतू सोनी जी से की सौजन्य मुलाकात

इंदौर। रणजीत टाइम्स के प्रधान संपादक गोपाल गावंडे ने संझा लोकस्वामी के प्रधान संपादक श्री जीतू सोनी जी से शिष्टाचार एवं सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर रणजीत टाइम्स के संभाग ब्यूरो राजेश धाकड़ भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, जनहित के मुद्दों, मीडिया की जिम्मेदारियों तथा समाज के प्रति पत्रकारों की भूमिका पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही निष्पक्ष, निर्भीक एवं जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता को और अधिक सशक्त बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह सौजन्य भेंट पत्रकारिता जगत में आपसी सहयोग, संवाद और सकारात्मक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।

दैनिक रणजीत टाइम्स

जिला एवं तहसील स्तर पर

एजेंसी देना है

अपना बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण के साथ हमें प्रेषित करें।

सम्पर्क करें

8224951278 :: 9827068888

'विकास का कोई शॉर्टकट नहीं', ढाई साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे विधायक प्रीतम सिंह लोधी

अतुल जैन

खनियांधाना। विकास के दावों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी गुरुवार को खनियांधाना पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, आमजन की समस्याएं सुनीं और बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, सड़क, आवास, धार्मिक स्थलों के विकास और नगर के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पिछोर विधानसभा अब पिछड़े क्षेत्र की पहचान छोड़ विकास की नई मिसाल बन रही है। पत्रकारों से बातचीत में विधायक लोधी ने कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि साफ नीयत, मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयासों से संभव होता है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में उनकी प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना रही, जिसका सकारात्मक परिणाम आज पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, जिस क्षेत्र का शैक्षणिक प्रदर्शन कभी लगभग 25 प्रतिशत के आसपास था, वह लगातार प्रयासों, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और सम्मानित करने की योजनाओं के चलते अब लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछोर विधानसभा आज पूरे चंबल संभाग में अग्रणी स्थान पर है।

विधायक ने बताया कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मेधावी छात्रों को चांदी के मेडल, ब्लेज़र तथा बाद में गोल्ड मेडल देने की पहल की गई। इन प्रयासों के कारण शिक्षा का माहौल बदला और क्षेत्र को सीएम राइज स्कूल जैसी

महत्वपूर्ण सौगात मिली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की एक छात्रा के प्रदेश की टॉप-10 सूची में स्थान प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर खनियांधाना में केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी समान रूप से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्षेत्र में एक हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 600 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि जारी हो चुकी है, जबकि शेष आवासों की प्रक्रिया जारी है।

विधायक लोधी ने बताया कि खनियांधाना नगर में लगभग 1.10 करोड़ रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा सीता पाठा क्षेत्र में भी एक करोड़ दस लाख रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कोटयाई में भगवान बिरसा मुंडा मंदिर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तथा भगवान श्रीकृष्ण मंदिर के विकास के लिए 36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास को समान प्राथमिकता दी जा रही है। नगर के ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि तालाब की सफाई, सौंदर्यीकरण, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित कर इसे शहर की पहचान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में सफाई और अव्यवस्था के संबंध में पूछे गए सवाल पर विधायक ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन और कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में शामिल हुए थे और भविष्य में भी यदि आवश्यकता पड़ी तो जनता के साथ मिलकर ऐसे अभियान चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि खनियांधाना को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित नगर बनाने तक उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इस अवसर पर सरपंच अशोक यादव, मंडल अध्यक्ष विवेक यादव, विधायक प्रतिनिधि भानु जैन चौधरी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पति जगदीश साहू, हिमांशु झा, रमाकांत पाठक, मृगेंद्र चौबे, सरदार परिहार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के आश्वासन पर समाप्त हुई जन संघर्ष समिति की भूख हड़ताल

गुलाना। जन संघर्ष समिति मध्यप्रदेश द्वारा तहसील कार्यालय, गुलाना परिसर में जन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आयोजित भूख हड़ताल प्रशासन के सकारात्मक हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक पहुंचे चार घंटे चली भूख हड़ताल की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं उपस्थित नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके बाद कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर त्वरित निराकरण कराया गया।

जन संघर्ष समिति मध्यप्रदेश के संस्थापक सदस्य अविनाश सिंह ने बताया कि आंदोलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या विभाग का विरोध करना नहीं, बल्कि आमजन की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान कराना था। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए जनहित के मुद्दों पर गंभीरता दिखाई गई, जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा है। अनुविभागीय अधिकारी ने समिति सयोंजक राजा भैय्या को आश्वास्त किया की गुलाना तहसील से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण किया जा रहा हैं राजा भैय्या ने एस डी एम को बताया की गुलाना तहसील में नागरिक किसान ग्रामीण बहुत परेशान हैं सीमांकन समय पर नहीं हो रहें दो सौ पचास के तहत आदेश होने के पश्चात भी किसानों को कब्जा नहीं मिल पा रहा हैं कोई भी काम समय पर नहीं हो रहें हैं चौकीदार तहसील चला रहें हैं बाबू सुनवाई नहीं करते हैं प्रकरणो में निराकरण नहीं हो पा रहें ग्रामीण चककर पर चककर लगा रहें पटवारी गिरदावर अपना कार्य समय पर नहीं कर रहें राजा भैय्या द्वारा बताई गई समस्याओं को तत्काल अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा निराकरण किया गया जन संघर्ष समिति ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। तथा सरपंच कालूराम जी द्वारा राजा भैय्या संजू पितले अविनाश सिंह पूंजीलाल हरलाल को जूस पिला कर भूख हड़ताल समाप्त करवाई सभा को सम्बोधित करते हुए अविनाश सिंह ने कहा कि जन संघर्ष समिति आगे भी जनता की आवाज़ बनकर कार्य करती रहेगी। यदि भविष्य में जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरती जाती है तो समिति लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से जनहित की लड़ाई जारी रखेगी। संजय पितले ने अपने उदबोधन में कहा की संगठन को मज़बूत करिए समस्याएं हम हल करवाएंगे अपने गाँव एवं आसपास के लोगों को समिति से जोड़िये हम आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष जारी रखेंगे अंत में राजा भैय्या ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा की जनता को संगठित कर जनता के लिए संघर्ष करने के लिए जन संघर्ष समिति बनाई गई हैं हमें जनता के लिए संघर्ष करना हैं हम लोग जनता के लिए हर क़दम क़दम पर संघर्ष करेंगे और निराकरण नहीं होने पर आगे तक संघर्ष जारी रखेंगे।

मारपीट से आहत युवक ने लगाई फांसी, तीन पर मामला दर्ज

दिव्यानंद अर्गल

गोहद। गोहद के वार्ड क्रमांक 16 गांधी नगर में 18 वर्षीय राजेश जाटव ने कथित मारपीट और सार्वजनिक अपमान से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि 28 जून की शाम पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी रामप्रकाश जाटव, उसके पुत्र कौशल जाटव और कोमल जाटव ने राजेश के साथ सार्वजनिक स्थान पर मारपीट की थी। घटना के करीब दो घंटे बाद राजेश ने अपने घर में फांसी लगा ली। थाना गोहद में मर्ग क्रमांक 14/26 की जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामप्रकाश जाटव, कौशल जाटव एवं कोमल जाटव के विरुद्ध धारा 108 एवं 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

रणजीत टाइम्स

राजकोट नगर निगम में 3 करोड़ के अतिक्रमण अभियान बिल पर सवाल, भुगतान रुका; जांच के लिए SIT गठित

राजकोट। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़े करीब 3 करोड़ रुपये के बिलों पर गंभीर सवाल उठने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने उनका भुगतान रोक दिया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में कई खर्चों को लेकर अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। जांच अधिकारियों के अनुसार, रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत नगर निगम से 200 मिलीलीटर की एक मिनरल वॉटर बोतल के लिए 8 रुपये का भुगतान दर्शाया गया, जबकि बाजार में इसी श्रेणी की प्रीमियम बोतल थोक में 3 रुपये से कम और खुदरा बाजार में करीब 5 रुपये में उपलब्ध है।

अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के खर्चों सहित अन्य मदों में भी बिलों की दरें और भुगतान प्रक्रिया की गहन जांच की आवश्यकता है। इसी वजह से स्टैंडिंग कमेटी ने फिलहाल भुगतान पर रोक लगाते हुए पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने का फैसला किया है। जांच दल संबंधित दस्तावेजों, बिलों, भुगतान रिकॉर्ड और रेट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की समीक्षा करेगा। यदि जांच में वित्तीय अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

सड़कें चमक रहीं, ज़िंदगियाँ बुझ रहीं...

सरकार ख़ामोश!

इंदौर विकास की दौड़ में आगे है, लेकिन रफ्तार की इस दौड़ में इंसानी ज़िंदगियाँ पीछे छूटती जा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिले के 31 ब्लैक स्पॉट पर पिछले साढ़े तीन वर्षों में 239 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 स्थान बेहद खतरनाक माने गए हैं। सवाल यह है कि जब इन जगहों की पहचान सरकार और प्रशासन को पहले से है, तो फिर मौत का यह सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा?

हर हादसे के बाद वही पुराना बयान-"जांच होगी", "सुधार किए जाएंगे", "निर्देश दे दिए गए हैं"। लेकिन सड़क पर उतरते ही सच्चाई सामने आ जाती है। कहीं अंधा मोड़, कहीं टूटी सड़क, कहीं रोशनी नहीं, कहीं संकेतक गायब। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ब्लैक स्पॉट पहले घोषित होते हैं, सुधार बाद में भी नहीं होते, लेकिन मौतें समय पर होती रहती हैं। सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन होता है, लेकिन यदि वर्षों से चिन्हित खतरनाक स्थानों को भी सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता, तो विकास के दावों का अर्थ क्या रह जाता है?

सवाल विपक्ष से नहीं, सत्ता से है। सवाल राजनीति से नहीं, जवाबदेही से है।

239 मौतें कोई आंकड़ा नहीं, 239 परिवारों का उजड़ना है।

क्या अगली समीक्षा बैठक में फिर केवल फाइलें पलटी जाएंगी, या इस बार उन सड़कों को भी देखा जाएगा जहाँ हर कुछ दिनों में किसी घर का चिराग बुझ जाता है?

सरकार कब तक ख़ामोश रहेगी? या अगली मौत का इंतज़ार है?

GAGAN के नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि, भारत बना दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल

नई दिल्ली। भारत के स्वदेशी सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम GAGAN (GPS Aided GEO Augmented Navigation) ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। यह प्रणाली भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करती है, जिनके पास विमानन क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक Satellite-Based Augmentation System (SBAS) उपलब्ध है।

GAGAN का विकास (ISRO) और (AAI) ने संयुक्त रूप से किया है। इसका उद्देश्य GPS की सटीकता बढ़ाना और विमानों को अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराना है। यह प्रणाली विमान संचालन के दौरान पायलटों को अत्यंत महत्वपूर्ण 'इंटीग्रिटी सूचना' (Integrity Information) उपलब्ध कराती है, जिससे नेविगेशन संबंधी त्रुटियों की तुरंत पहचान हो जाती है और उड़ान सुरक्षा बेहतर होती है। GAGAN विशेष रूप से लैंडिंग, टेकऑफ और चुनौतीपूर्ण मौसम की परिस्थितियों में विमान संचालन को अधिक सुरक्षित बनाता है।

वर्ष 2015 से परिचालन में मौजूद GAGAN के साथ भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद इस उन्नत तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने वाला दुनिया का चौथा क्षेत्र बन गया। यह उपलब्धि देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि GAGAN न केवल भारतीय विमानन क्षेत्र को नई मजबूती देगा, बल्कि भविष्य में ड्रोन, सटीक मानचित्रण, आपदा प्रबंधन और अन्य नेविगेशन आधारित सेवाओं में भी इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ेगी। यह उपलब्धि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को नई गति देने वाला एक अहम कदम भी मानी जा रही है।

ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का सहज मार्ग है सहजयोग

भारतीय अध्यात्म का मूल संदेश यह है कि ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो नाम हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप सत्, चित् और आनंद है—सत् अर्थात शाश्वत और अविनाशी अस्तित्व, चित् अर्थात पूर्ण चेतना एवं ज्ञान, तथा आनंद अर्थात असीम और नित्य परमानंद। यही वह परम सत्य है, जिसे जान लेने पर मनुष्य जीवन के बाहरी संघर्षों, अस्थिरताओं और सीमाओं से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। आत्मसाक्षात्कार का अर्थ इसी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जहाँ साधक अज्ञान, भय, तनाव और सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने दिव्य स्वरूप को जानता है।

इसी आत्मबोध की सहज, सरल और वैज्ञानिक साधना का मार्ग है सहजयोग, जिसे परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने विश्व को प्रदान किया। सहजयोग का उद्देश्य किसी जटिल कर्मकांड, कठिन तपस्या या बाह्य प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति कुंडलिनी के जागरण के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार का अनुभव कराता है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तो साधक अपने भीतर एक नई चेतना, एक नई स्थिरता और एक नई संवेदनशीलता का अनुभव करता है। यह अनुभव केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहार और जीवन-दृष्टि में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

सहजयोग की विशेषता यह है कि यह हर आयु, हर वर्ग और हर पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए सुलभ है। साधक को केवल खुले मन, नियमित अभ्यास और आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना सीखता है, जिससे तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक स्थिरता विकसित होती है और जीवन में आंतरिक प्रसन्नता का संचार होता है। अनेक साधकों ने यह अनुभव किया है कि सहजयोग के नियमित अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पारिवारिक संबंधों, कार्यक्षमता और सामाजिक व्यवहार में भी सकारात्मक सुधार आता है।

आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग सहजयोग के माध्यम से ध्यान, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और जीवन-शैलियों के लोग इस साधना से जुड़कर अपने भीतर संतुलन और आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। सहजयोग यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। यदि आप भी परमात्मा के असीम प्रेम, आशीर्वाद और ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं तथा अपनी आत्मा का योग परमात्मा से घटित करना चाहते हैं, तो आज ही सहजयोग से जुड़ें। यह एक ऐसा मार्ग है जो सरल भी है और गहन भी, सहज भी है और परिवर्तनकारी भी। सहजयोग पूर्णतः निःशुल्क है। अपने निकटतम सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा www.sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं।

करैरा बाजार में शराब के नशे में हूटर बजाते दौड़ा रहा था 25 लाख की टाटा सफारी, पुलिस ने चालक समेत मालिक पर की कार्रवाई, वाहन जब्त

हेमंत भार्गव

करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा थाना पुलिस ने बाजार क्षेत्र में शराब पीकर खतरनाक तरीके से हूटर बजाते हुए टाटा सफारी चलाने वाले चालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 25 लाख रुपये कीमत की टाटा सफारी कार को जब्त कर लिया तथा वाहन से अवैध हूटर भी निकालकर जब्त किया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उईके एवं प्रभारी एसडीओपी करैरा प्रशांत शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस सहायता केंद्र के पास करैरा बाजार में टाटा सफारी क्रमांक एमपी 04 सीएस 3743 को शराब के नशे में खतरनाक तरीके से चलाते हुए एवं हूटर बजाते पाए जाने पर चालक अरविंद यादव निवासी थाना जिगना, जिला दतिया के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 185, 119/190(2) एवं 51/177 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान वाहन के पीछे नंबर प्लेट नहीं मिली। वहीं वाहन का बीमा भी नहीं पाया गया, जिसके चलते वाहन मालिक अर्जुन यादव निवासी खैराई, करैरा के विरुद्ध धारा 146/196 एमवी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन और हूटर को जब्त कर चालान माननीय न्यायालय करैरा में पेश किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई, उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र यादव, आरक्षक हरेंद्र गुर्जर, मत्स्येंद्र गुर्जर एवं राघवेंद्र पाल की सराहनीय भूमिका रही।

देपालपुर न्यायालय का बड़ा फैसला: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सोहन पवार के परिजनों को मिलेगा 63.72 लाख का मुआवजा

राजेश धाकड़

देपालपुर न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार वर्ष पूर्व हुए सड़क हादसे के मृतक सोहन पवार के परिजनों के पक्ष में 63,72,674 (तिरेसठ लाख बहत्तर हजार छह सौ चौहत्तर रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने यह राशि बस चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना के एवज में तय की है।तेज रफ्तार बस ने मारी थी टक्करघटना चार वर्ष पुरानी है। ग्राम गिरोड़ निवासी सोहन पवार अपने पाड़े (भैंस का बच्चा) को लेकर खेत से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बेटमा की तरफ से आ रही एक बस के चालक ने वाहन को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सोहन पवार और उनके पाड़े को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से सोहन पवार को शासकीय

अस्पताल देपालपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिवक्ताओं की रही मुख्य भूमिका ;- मृतक सोहन पवार के परिजनों को न्याय दिलाने और क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देपालपुर के समक्ष क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस कानूनी लड़ाई में परिजनों की ओर से अधिवक्ता विपिन चंद्र धाकड़ एवं राजेश आशापुरे ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के सामने मजबूती से तथ्य रखे और बस के स्वामी, चालक व बीमा कंपनी को इस मामले में पक्षकार बनाया। ब्याज सहित 30 दिनों में भुगतान का आदेश ;- न्यायालय ने आवेदकों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि वह 63,72,674 की यह क्लेम राशि 30 दिनों के भीतर जमा करे। इसके साथ ही, न्यायालय ने परिजनों को बड़ी राहत देते हुए यह भी आदेश दिया है कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि (09 दिसंबर 2022) से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक इस पूरी अवार्ड राशि पर 6% की वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाए।

पंजाब चुनाव 2027: भगवंत मान को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, संगठन में साधे सभी बड़े समीकरण

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा दांव चला है। पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखते हुए वरिष्ठ नेताओं चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस रणनीति का उद्देश्य गुटबाजी को कम करना और सभी सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जातीय समीकरणों को साधना है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि मजबूत और संतुलित संगठन के दम पर पार्टी पंजाब में दोबारा अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सकती है। दलित, जाट सिख, हिंदू और शहरी मतदाताओं सहित विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश के तहत नेताओं को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं।

सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आशा किरण

बालगृह में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

डीएसपी अजाक सुश्री शिवा पाठक ने बच्चों को किया जागरूक, 1930 डूडल मेकिंग एवं स्ट्रांग पासवर्ड प्रतियोगिता भी संपन्न

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित "सेफ क्लिक अभियान 2.0" के अंतर्गत जिले में साइबर अपराधों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डीएसपी अजाक सुश्री शिवा पाठक द्वारा आशा किरण बालगृह में बच्चों एवं फैकल्टी के मध्य साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुश्री शिवा पाठक ने उपस्थित बच्चों एवं फैकल्टी को साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप, ऑनलाइन ठगी के सामान्य तरीकों, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, फर्जी लिंक एवं कॉल से सावधान रहने, ओटीपी/पासवर्ड साझा न करने तथा किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं निकटतम पुलिस से संपर्क करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।कटनी पुलिस द्वारा आमजन, विद्यार्थियों एवं विभिन्न संस्थानों में लगातार साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके और साइबर अपराधों की रोकथाम में जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।

15 दस्तावेज भी नहीं बचा सके, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शख्स को माना विदेशी; जानिए क्यों

गुवाहाटी। असम में एक व्यक्ति 15 अलग-अलग दस्तावेज पेश करने के बावजूद अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका। ने के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे विदेशी घोषित किया।

मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति ने पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल पहचान संबंधी दस्तावेज भारतीय नागरिकता का अंतिम और पर्याप्त प्रमाण नहीं माने जा सकते।

कोर्ट ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण यह साबित करना होता है कि संबंधित व्यक्ति या उसके पूर्वज निर्धारित कानूनी कट-ऑफ तिथि से पहले भारत में वैध रूप से रह रहे थे।

प्रस्तुत दस्तावेजों में आवश्यक कड़ियां (Link Documents) और पूर्वजों से संबंध स्थापित करने वाले विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिल सके। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोहराया कि पैन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र अपने आप में भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं, यदि उनसे नागरिकता संबंधी कानूनी शर्तें पूरी तरह सिद्ध नहीं होतीं। यह फैसला असम में नागरिकता से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की वैधानिक अहमियत और उन्हें साबित करने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

कटनी बस स्टैंड में परिवहन एवं यातायात विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, 41 यात्री बसों की हुई जांच, 7 पर लगा जुर्माना, 8 की फिटनेस निरस्त

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी। जिले में सड़क एवं यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा कटनी बस स्टैंड पर संयुक्त सघन जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान के दौरान कुल 41 यात्री बसों का निरीक्षण किया गया। जांच में 7 बसों में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई गईं, जिन पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 7 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। संबंधित वाहन संचालकों को भविष्य में सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जांच के दौरान एक गंभीर अनियमितता भी सामने आई, जिसमें 8 बसों में आपातकालीन निकास इमरजेंसी गेटके सामने सीटें लगाई गई थीं। इसे यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित बसों की फिटनेस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधार और पुनः निरीक्षण के बाद ही इन बसों की फिटनेस बहाल की जाएगी। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल ने कहा कि यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इमरजेंसी निकास को अवरुद्ध करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बस संचालकों से नियमित वाहन रखरखाव एवं सभी वैधानिक दस्तावेज अद्यतन रखने की अपील की।

यातायात विभाग के अधिकारियों ने वाहन चालकों एवं परिचालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि यात्रियों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी भी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में परिवहन नियमों के उल्लंघन, ओवरलोडिंग तथा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों के विरुद्ध ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे, ताकि सुरक्षित एवं व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महिला से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

विजयराघवगढ़ पुलिस की कार्यवाही

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी। विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक ;30/06/2026 को विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र की पीड़िता महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कटनी महिला थाने में जीरो एफआईआर करने के उपरांत थाने में अपराध धारा 296 (6),(332(b) 351 (3),64 (1) 78(2) bns की असल कायमी की गई। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वह एक शादीशुदा महिला है और आरोपी की पत्नी पीडिता की सहेली है इसी वजह से आरोपी और पीड़िता का आपस में संपर्क हुआ। आरोपी पीड़िता को करीब दो माह से बात करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। पीड़ित महिला का पति कथा वाचने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए घर से बाहर रहते हैं इसी का फायदा उठाकर आरोपी प्रशांत उर्फ शेरा मिश्रा पिता श्री सुंदरलाल मिश्रा उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम बडगइयां सलैया थाना विजयराघवगढ़ के द्वारा, घर पर अकेली महिला से बलात्कार किया गया। पीड़ित महिला ने पति के वापस आने पर पति को पूरी घटना बताई और फिर महिला और उसके पति ने कटनी महिला थाने में रिपोर्ट की। पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शेरा मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां पर उसे माननीय न्यायालय के द्वारा न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस कार्यवाही मे विशेष भूमिका - उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरी.अभिषेक चौबे, उनि रामकुमार झारिया, एएसआई जगदीश पांडे आरक्षक पप्पू प्रजापति, अंजनी झा एवं आरक्षक चालक मज्जू कोल का विशेष योगदान रहा।

संतोष बघेल प्रकरण:

एसपी कार्यालय का घेराव, दोषी

पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

दिव्यानंद अर्गल

भिंड। मेहगांव थाना क्षेत्र में मृतक संतोष बघेल के परिजनों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी महेश शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने तथा निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि न्याय की मांग कर रहे पीड़ित परिवार पर बल प्रयोग किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दोषी कौन है—न्याय की मांग करने वाला पीड़ित परिवार या उन पर लाठियां बरसाने वाले पुलिसकर्मी। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को न्याय मांगने का अधिकार है और उनकी आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि टीआई महेश शर्मा एवं अन्य संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मृतक संतोष बघेल के परिवार को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की जाए तथा किसी भी दोषी को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण न मिले। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट रायसिंह बौद्ध ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

जलप्लावन से निपटने

स्वच्छता दूतों ने संभाला मोर्चा

नवल किशोर कुशवाहा

पहली बारिश में निगम प्रशासन रहा अलर्ट, वर्षा जल निकासी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में की त्वरित कार्रवाई

कटनी । मानसून की पहली बारिश के साथ ही शहर में जलभराव की संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। नागरिकों को जलभराव से राहत दिलाने एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को नगर निगम के स्वच्छता दूतों एवं स्वास्थ्य अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर वर्षा जल निकासी की व्यवस्था संभाली तथा जहां भी आवश्यकता महसूस हुई, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी की निर्बाध निकासी सुनिश्चित की गई। नगर निगम द्वारा वर्षा काल से पूर्व ही नाले-नालियों की व्यापक सफाई का अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी का परिणाम रहा कि पहली बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने सफलता मिल सकी। स्वच्छता दूतों द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों एवं जलभराव संभावित स्थानों का निरीक्षण कर चोक नाले-नालियों की तत्काल सफाई कराई गई तथा जल निकासी मार्गों में बारिश के दौरान बहकर आए अवरोध उत्पन्न करने वाले कचरे, पॉलीथिन एवं मलबे को हटाया गया। जिन स्थानों पर वर्षा जल का जमाव दिखाई दिया, वहां स्वच्छता दूतों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक संसाधनों के माध्यम से तत्काल पानी की निकासी कराई, जिससे नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। बारिश के दौरान भी निगम का स्वास्थ्य अमला लगातार फील्ड में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रहा। नगर निगम प्रशासन द्वारा वर्षा काल के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थान पर जलभराव की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा अथवा मलबा न डालें तथा शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें। नागरिकों के सहयोग एवं निगम प्रशासन की सतत निगरानी से वर्षा ऋतु के दौरान जलभराव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा तथा शहरवासियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी।

खनियांधाना पुलिस ने चलाया 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान, सनराइज स्कूल में बच्चों व नागरिकों को किया साइबर अपराध के प्रति जागरूक

अतुल जैन

डिजिटल अरेस्ट, OTP व UPI फ्रॉड से बचाव के बताए तरीके, SP यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में चल रहा प्रदेशव्यापी अभियान

खनियांधाना। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0' के तहत थाना खनियांधाना पुलिस ने बुधवार को सनराइज स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। थाना प्रभारी निरीक्षक केदार सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्कूली बच्चों एवं आम नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, KYC फ्रॉड, OTP शेयरिंग, UPI धोखाधड़ी एवं निवेश के नाम पर ठगी जैसे साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, OTP किसी से साझा न करें और संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। यह अभियान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा एवं एडीजी साइबर ए. साई मनोहर के निर्देशन में चलाया जा रहा है। ग्वालियर जोन आईजी अरविंद कुमार सक्सेना एवं डीआईजी असित यादव द्वारा जोन में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन में जिले में लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में थाना खनियांधाना पुलिस ने यह कार्यक्रम संपन्न कराया।

सराहनीय भूमिका:

कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक केदार सिंह यादव, उनि छाया राय, सउनि रामसिंह भिलाला, आरक्षक अनूप कुमार की विशेष भूमिका रही।

गौ मांस के अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने दोनों आरोपियों को रासुका में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए

राजेश धाकड़

इंदौर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में मांस का अवैध रूप से क्रय विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने उक्त दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जिन कुख्यात आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया गया है उनमें इमरान पिता अनवर खटखट एवं मोहम्मद हाशिम पिता मोहम्मद याकुब, दोनों निवासी बंडाबस्ती, थाना महू शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर लंबे समय से मारपीट, धमकी, गोवंश वध, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। 29 मई 2026 को बंडाबस्ती में गोवंश वध के मामले में दर्ज अपराध के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। दोनों आरोपियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा दोनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है।

5.30 बजे परीक्षा खत्म,5.35 पर रिजल्ट घोषित!

कर्नाटक यूनिवर्सिटी में 5 मिनट में कॉपी चेकिंग पर सवाल, जांच की मांग तेज

कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी में परीक्षा और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि यहां 5.30 बजे परीक्षा समाप्त हुई और मात्र 5.35 बजे परिणाम जारी कर दिए गए, जिससे सिर्फ 5 मिनट में कॉपी चेकिंग और मूल्यांकन पर संदेह गहराने लगा है।

जानकारी के अनुसार

यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2022-23 में छठे सेमेस्टर के करीब 41,835 छात्रों का परिणाम लगभग 10 दिनों के भीतर घोषित किया था। इसके बाद 2023-24 और 2024-25 सत्रों में भी परिणाम घोषित करने में 10 से 11 दिनों का समय लगा। लेकिन 2025 के फाइनल वर्ष में अचानक प्रक्रिया बदल गई और महज 1 घंटे के भीतर परिणाम जारी

कर दिए गए।

इतनी तेज़ी से रिजल्ट आने के बाद छात्र और शिक्षा जगत में आश्चर्य और संदेह दोनों बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने कम समय में बड़ी संख्या में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तकनीकी रूप से लगभग असंभव है, जब तक कि पूरी प्रक्रिया पहले से ऑटोमेटेड या प्री-प्रोसेस्ड न हो। मामले के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छात्र संगठनों ने भी इस पर जवाब मांगा है और मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच की मांग की है। फिलहाल यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि रिजल्ट इतनी तेजी से कैसे जारी किया गया और क्या प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है।

महाराष्ट्र की राजनीति में नई रणनीति की चर्चा, शिंदे-फडणवीस समीकरण पर सियासी अटकलें तेज

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सत्ता संतुलन और नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। महायुति गठबंधन के भीतर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे की बढ़ती राजनीतिक भूमिका कहीं न कहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बीजेपी हाईकमान का उद्देश्य राज्य में सभी प्रमुख सहयोगी दलों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना माना जा रहा है, ताकि किसी एक नेता या गुट का अत्यधिक प्रभाव न बन सके। इसी संदर्भ में शिंदे की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई थी। दूसरी ओर, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गए। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व हर स्तर पर संतुलन की रणनीति अपना रहा है, ताकि गठबंधन मजबूत बना रहे और किसी भी तरह का आंतरिक टकराव चुनावी संभावनाओं को प्रभावित न करे। हालांकि, बीजेपी या शिंदे गुट की ओर से इस तरह की किसी भी रणनीति की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल यह पूरा मामला राजनीतिक अटकलों और विश्लेषणों पर आधारित है, जिस पर आने वाले समय में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

दिल्ली में पहली बार बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट, 38 हजार करोड़ के वित्तीय खुलासे की संभावना

दिल्ली सरकार ने राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ऑडिट का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। इस कदम को बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार, इस ऑडिट के जरिए करीब 38,000 करोड़ रुपये के "रेगुलेटरी एसेट्स" से जुड़े मामलों की गहन जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि इन आंकड़ों के पीछे की वास्तविक वित्तीय स्थिति और प्रबंधन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह ऑडिट केवल पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजधानी के बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आधारशिला साबित होगा। उनके अनुसार, इससे उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से डिस्कॉम्स की वित्तीय संरचना और रेगुलेटरी एसेट्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में CAG ऑडिट से इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच संभव होगी और यह स्पष्ट हो सकेगा कि खर्च और देनदारियों का वास्तविक स्वरूप क्या है। फिलहाल इस फैसले को दिल्ली के बिजली सेक्टर में एक बड़े सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

प्रसिद्ध झील में बड़ा हादसा,

पर्यटकों से भरी नाव पलटी; एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 3 लापता

रेस्क्यू अभियान जारी, हादसे के कारणों की जांच शुरू

नई दिल्ली। एक प्रसिद्ध पर्यटन झील में बड़ा हादसा उस समय हो गया, जब पर्यटकों से भरी एक नाव अचानक पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य अब भी लापता हैं। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत दल ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे या हादसा खराब मौसम और तेज हवा के कारण हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। गोताखोरों और राहत टीमों द्वारा लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद झील में नौका संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों और नाव संचालकों की लापरवाही की भी जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। इस दुखद घटना के बाद पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और नाव संचालन के नियमों को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

बदला ग्लोबल ट्रेड का भूगोल!

कभी कच्चा तेल देने वाला रूस, अब भारत से क्यों खरीद रहा है पेट्रोल?

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी भारत को बड़े पैमाने पर कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) बेचने वाला रूस अब भारत से पेट्रोल और अन्य परिष्कृत ईंधन (Refined Fuels) भी खरीद रहा है। यह बदलाव यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक ऊर्जा व्यापार के नए समीकरणों का परिणाम माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस ने रियायती दरों पर भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल बेचना शुरू किया। भारतीय रिफाइनरियों ने इस सस्ते कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में बदलकर घरेलू जरूरतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात बढ़ाया।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया है। वहीं रूस के कुछ क्षेत्रों में रिफाइनिंग क्षमता पर दबाव, रखरखाव कार्य और ईंधन की मांग को देखते हुए भारत से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद भी बढ़ी है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि आज वैश्विक तेल व्यापार केवल उत्पादक और खरीदार के पारंपरिक रिश्ते तक सीमित नहीं है। कई देश कच्चा तेल आयात कर उसे रिफाइन करने के बाद दूसरे देशों को तैयार ईंधन निर्यात करते हैं। भारत की आधुनिक रिफाइनिंग क्षमता और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने उसे इस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार,

यह घटनाक्रम दर्शाता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा व्यापार अधिक लचीला और व्यावसायिक होता जा रहा है। इससे भारत की रिफाइनिंग क्षमता और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होकर उभरी है।

उद्घाटन के 2 महीने बाद ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर पड़े गड्ढे

कांग्रेस ने कहा-'जनता के लिए घातक है मोदी सरकार'

नई दिल्लीः हाल ही में आम जनता के लिए खोले गए 12,000 करोड़ की लागत से बने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही एक्सप्रेसवे पर कई जगह गहरे गड्ढे होने और सड़क धंसने की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस मुद्दे को लपकते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब निर्माण का आरोप लगाते हुए चौतरफा हमला बोला है।

क्या है पूरा मामला?-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली से देहरादून की दूरी को महज 2 से ढाई घंटे में समेटने वाले इस महत्वकांक्षी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इसके शुरू होने के दो महीने के भीतर ही सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा शेयर किए जा रहे वीडियो में सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। यात्रियों का आरोप है कि एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां इन गड्ढों के कारण अपना संतुलन खो रही हैं। कई चालकों ने शिकायत की है कि अचानक सामने आए गड्ढे की वजह से

उनकी गाड़ियों के अलॉय व्हील तक टेढ़े हो गए हैं और यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है

कांग्रेस का तीखा पलटवार

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की 'स्पीड और स्केल' की नीति पर तंज कसते हुए इसे भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत बताया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी कर कहा गयाः » "12,000 करोड़ की भारी-भरकम लागत से बने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए अभी ठीक से दो महीने भी नहीं बीते कि यह 'एक्सीडेंट जोन' में तब्दील हो गया है। पहली ही बारिश में एक्सप्रेसवे की सड़कें उखड़ गईं और बड़े-बड़े गड्ढे नजर आने लगे हैं। मोदी सरकार का यह मॉडल देश और जनता की जेब व जान दोनों के लिए घातक साबित हो रहा है।"

» कांग्रेस ने मांग की है

इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि जनता के पैसे का इस कदर दुरुपयोग क्यों किया गया।

NHAI और प्रशासन की स्थिति

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और विपक्ष के हमलों के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) हरकत में आया है।

प्रभावित हिस्सों पर आनन-फानन में मिट्टी और गिट्टी डालकर गड्ढों को अस्थाई रूप से भरने (पैचवर्क) का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि, तकनीकी जानकारों का कहना है कि इतने आधुनिक और महंगे एक्सप्रेसवे का दो महीने में इस तरह बैठ जाना सीधे तौर पर निर्माण की गुणवत्ता और कंक्रीट मिक्सिंग में बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। इस रूट पर सफर करने वाले यात्री अब डरे हुए हैं, क्योंकि 100 किमी/घंटे की रफ्तार वाले इस एक्सप्रेसवे पर जरा सी चूक या छोटा सा गड्ढा भी जानलेवा साबित हो सकता है।